फाइल नं0-71-1002/8/2024

संख्या-51/2024/I/516984/2024

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 12 मार्च, 2024**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्र सहायतित योजनान्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, मीरजापुर में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2023-24/779, दिनांक 09.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा केन्द्र सहायतित योजनान्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, मीरजापुर में नर्सिंग कालेज की स्थापना **हेतु** रू0 1002.62 लाख का आगणन उपलब्ध कराते हुए पी0एफ0ए0डी0 से मूल्यांकित कराने एवं प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार किये जाने का अनुरोध किया गया।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-जेड-16015/2/2023-एन, दिनांक 28.04.2023 द्वारा केन्द्र सहायतित योजना "Establishment of new medical colleges attached with existing District/Referral hospitals" के अंतर्गत उ0प्र0 प्रदेश के 27 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में "Scheme for Augmenting Nursing Education-Establishment of new College of Nursing (CoN) in co-location with Medical College" के अंतर्गत नर्सिंग कालेज की स्थापना का निर्णय लिया गया। उक्त योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रति नर्सिंग कालेज की लागत रू0 10.00 करोड़ निर्धारित की गयी है, जिसका फ़ण्डिग पैटर्न 60:40 (केन्द्रांश+राज्यांश) है। उक्त के क्रम में उप निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-जेड.28015/89/2023-एन, दिनांक 21.08.2023 द्वारा केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत 27 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लागत रू0 10.00 करोड़ (प्रति कालेज) के सापेक्ष प्रति कालेज रू0 2.00 करोड़ अर्थात् कुल रू0 54.00 करोड़ की धनराशि केन्द्रांश के रूप में उपलब्ध करायी गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत **स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, मीरजापुर** में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु प्रायोजना रचना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित लागत रू0 992.17 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत् पूँजीपक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-105-01-28-राजकीय मेडिकल कालेज/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग कालेज हेतु मानक मद-24-वृहत निर्माण कार्य मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष प्रश्नगत परियोजना हेतु प्रथम किश्त के रूप में **रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र)** की धनराशि केन्द्रांश के रूप में किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से एस0एन0ए0 खाते में हस्तांतरित की जायेगी।
2. प्रयोजनान्तर्गत नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाए।
4. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत् मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं एवं उच्च विशिष्टियों को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्त्रदायित्व प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का होगा।
5. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रायोजनान्तर्गत फायर फाइटिंग सम्बन्धी कार्य नेशनल बिल्डिग कोड के अनुरूप है।
6. प्रायोजनानतर्गत प्रस्तावित कार्यो की लागत बॉट आइटम (लिफ्ट) सहित रू0 770.19 लाख पर 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 138.63 लाख आंकलित की गयी है, जो वास्तविकता के आधार पर अनुमन्य होगी। कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 अलग से सम्मिलित न हो। उक्त मद में वास्तविकता के आधार पर ही धनराशि अनुमन्य होगी।
7. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
8. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाए।
9. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित विशिष्टियों एंव प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, क्षेत्रफल में वृद्धि तथा उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
10. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एंव भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11.प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजनास्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।/

12.प्रायोजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13.वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनॉक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14.प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

15.कार्य की गुणवत्ता , मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।

16.स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा , जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

17.अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

18.कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

19.संबंधित परियोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050128 राजकीय मेडिकल कालेज स्वायत्तशासी राज्य चिकित्सा /महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज (के.60/रा.40-के.) मानक मद 24 वहृत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3- 427/दस-2023-24, दिनांक- 06 मार्च, 2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

एस0 पी0 सिंह
उप सचिव।

संख्या व तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या-जेड-16015/2/2023-एन, दिनांक 28.04.2023 के संदर्भ में।
2. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. उप निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या-जेड.28015/89/2023-एन, दिनांक 21.08.2023 के संदर्भ में।
4. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, मीरजापुर।
5. निदेशक, कनस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज जल निगम, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, मीरजापुर।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, मीरजापुर।
9. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

एस0 पी0 सिंह

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।